out autonomous bodies and guarantee organisations under the Pension Scheme of 1972 respectively, if so, what are the details of the proposal?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) of THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) A pension scheme is in operation since 24-10-81 for the employees of Export Inspection Council and Export Inspection Agencies. As regards extension of the Pension Scheme to the autonomous and guarantee organisations, no general decision has been taken by the Government. As and when such a decision is taken, the question of extending the Pension Scheme for the employees of other autonomous bodies and guarantee organisations functioning under the administrative control of the Ministry of Commerce will be examined.

नये नवोदय विद्यालय खोलना

1124. **श्री मंवर लाल पंवार:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में और अधिक नवोदय विद्यालय खोलने की सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): नवोदय विद्यालय की योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है । सबसे पहले राज्य सरकार की पेशकश के आधार पर स्थान का चयन किया जाता है । विद्यालय चलाने के लिए संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रारम्भ में निःशुल्क तीस एकड़ भूमि और भवन तथा अन्य अवस्थापनाओं की व्यवस्था की जाती है। जहां तक संभव होगा इन विद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा । अब तक देश में 275 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं । नवोदय विद्यालय खोलना समग्र संसाधनों की उपलब्धता और प्रशासनिक मुद्दों के अतिरिक्त संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकार के प्रस्ताव पर आधारित होता है जिसे प्रारम्भ में 2–3 वर्षों के लिए विद्यालय चलाने हेतु निःशुल्क 30 एकड़ उपयुक्त भूमि, पर्याप्त भवन और अन्य अस्थापनाओं की व्यवस्था करनी होती है ।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश

1125. **श्री मंवर लाल पंवार:** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 1 सितम्बर, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 4406 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्ति हेतु पिछड़े वर्गों के कितने पात्र व्यक्तियों के नाम विचारार्थ भेजे थे और उनमें से कितने व्यक्तियों को न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्त किया गया था ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गई और उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े वर्गों से कितने न्यायाधीश संबंधित थे ; और

(ग) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की विद्यमान रिक्तियों पर नियुक्तियां करते समय सरकार उपरोक्त स्थिति पर विशेष ध्यान देने का विचार रखती है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 124 और 217 के अनुसार की

जाती हैं, जिनमें किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध नहीं है । अतः उच्च न्यायालयों में नियुक्तियां करते समय, जाति या समुदाय से संबंधी कोई जानकारी नहीं मांगी जाती है ।

(ख) तारीख 1-10-88 से अभी तक राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थायी/अपर न्यायाधीशों की नौ नई नियुक्तियां की गई हैं, इनमें एक न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति का है और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का कोई न्यायाधीश नहीं है ।

(ग) राज्यों के मुख्य मंत्रियों और राज्यपालों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे जहां तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, आदि से संबंधित ऐसे व्यक्तियों का पता लगाएं जो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों, जिससे कि उच्च न्यायालय में उन्हें उसने बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जा सके जैसा इस समय है ।

Production Target of Janata Cloth

1126. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what was the production target for janata cloth for the year 1990-91 and how much was produced; and

(b) what is the production target of janata cloth for the year 1991-92?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) During the year 1990-91, a production of 476.38 million square metres of janata cloth was achieved against the target of 600 million square metres.

(b) The target for production of janata cloth for the year 1991-92 has been fixed at 450 million square metres.

Indian Projects pending for World Bank Assistance

1127. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the details of Indian projects pending for World Bank assistance?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): Details of project proposals currently under active consideration for World Bank assistance are given in the enclosed statement. However, projects which would be finally tied-up for World Bank group assistance, the extent and timing of such assistance would depend on the detailed project preparation, firming up of the size and scope of individual projects, resource commitment by the Central Government and the State Government and other related factors.

Statement

Sl. No.	Name of the project with detail
1	West Bengal Forestry (Forestry II) project to support comprehensive approach to forest resource management mainlyin affore tation horticuture and silvpastur development on degeaded forest land.
2	Maharashtra State Forestry to support as comprzhensive approach to forestry resources managrment.
3	Shrimp and Fish Culture through development of brackish water shrimp ponds, fresh water fish in ponds and reservoi in West Bengal Orissa and Arddhra Pradesh.